

DPSP - राज्य के नीति निर्देशक तत्व

निर्देशक तत्वों की आलोचना -

1. कृ. सी. गाह के अनुसार 'राज्य के DPSP एक ऐसा चेहरा है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है'
2. DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
3. DPSP को भारतीय संविधान ने सुलभता से घोषित किया है लेकिन उन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता।
4. DPSP अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद / संघर्ष का कारण बन जाते हैं।
5. DPSP में Art-44 समान नागरिक संरक्षा को लागू भी लागू नहीं किया गया।
6. DPSP का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिन्से वह निर्देशित होते हैं।

DPSP में किए गए संशोधन

- 42 वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें Art 39 क, 43 क तथा 48 क को शामिल किया गया है।
- 42 वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से Art 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है।
- Art 45 राज्य प्रारंभिक शैक्षणिक नीति देकर रख कर सभी बच्चों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए

उपास करेगा ।" यह 86 वें सं संसदी अधिनियम 2002 की तहत धारा-3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

- 97 वें सं संसदी अधिनियम 2011 के माध्यम से Art 43 'ख' में 'सहकारी समिति' शब्द को जोड़ा गया है।

मूल अधिकार व निर्देशक तत्वों में संशोधन

संवैधानिक व्यवस्था में DPSP और FRs में कई ऐसे बिंदु दृष्टिगोचर होते हैं, जिन पर अलग-अलग धाराएं लागू होती हैं -

- Art 82 के तहत FRs न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाए गए हैं। Art 37 - DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 1951 के संसदी अधिनियम द्वारा बनाए गए संसदी अधिनियम न्यायालय के फैसले का अर्थ नहीं है।

- केरल शिक्षा विधेयक 1959 के तहत न्यायालय को कोशिकाओं का महत्व बनाए रखने के लिए समन्वयकारी निर्देशन का सिद्धांत अपनाया ।

- 42 वें सं संसदी अधिनियम 1976 में सभी DPSP को Art 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई ।

- मिमर्का मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में 42 वें संसदी अधिनियम पर DPSP की वरीयता को समाप्त कर DPSP व FRs में संतुलन को संविधान के मूल ढांचा को ध्यान में रखा गया ।

वर्तमान में Art 39(ख) और 39(ग) में उल्लिखित DPSP को FRs के Art 14, 19 पर वरीयता दी गई है।
श्रम सुधार, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का गठन, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा अभिधान, वन्य जीवों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग में सभी व्यवहारिक योजनाओं में DPSP को ही आधार बनाया गया है।